अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और

621

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

अर्चना पुरी से पहले, जे.

अशोक कुमार शर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

राकेश कुमार शर्मा और अन्य-उत्तरदाता

2020 की सी. आर. संख्या 1974

19 मार्च, 2024

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 8, आर. 6ए से 6जी-प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा-याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा लड़े गए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्थापित स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा-प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों से इनकार करते हुए किया गया जवाबी दावा-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया मुकदमा यू/ओ 9 नियम 8, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर जवाबी दावा जारी रहा - प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर जवाबी दावे को खारिज करने की मांग के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया-चुनौती दी गई-आयोजित, प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादियों के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है-सह-प्रतिवादी न तो जवाबी दावे के लिए लिखित बयान दायर कर सकता है और न ही उसके खिलाफ सह-प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी दावे को हटाने के लिए आवेदन कर सकता है-संशोधन की अनुमति है। अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वादी के दावे के खिलाफ जवाबी दावा दायर किया जा सकता है और इसे वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में दायर किया जा सकता है। हालांकि, उपरोक्त प्रावधान के आलोक में, मुकदमे में एक प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी, नियम 6ए (3) में निहित प्रावधान के आगे के अवलोकन में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा दायर किया जाता है, तो वादी जवाबी दावे के जवाब में लिखित बयान दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा, नियम 6सी वादी को प्रतिदावे के संबंध में मुद्दे तैयार होने से पहले प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावे पर आपत्ति उठाने का अधिकार देता है और वादी यह दावा कर सकता है कि प्रतिवादी के प्रतिदावे को उसके मुकदमे से बाहर रखा जाए और प्रतिदावे को दायर करने वाला प्रतिवादी, यदि चाहे तो एक अलग मुकदमा दायर कर सकता है। इसी तरह, नियम 6ई में प्रावधान है कि यदि वादी जवाबी दावे का जवाब दाखिल करने में चूक करता है, तो अदालत वादी के खिलाफ, उसके खिलाफ किए गए जवाबी दावे के संबंध में फैसला सुना सकती है। यहां तक कि नियम 6एफ में यह प्रावधान है कि जवाबी दावे में दी जाने वाली राहत वादी के खिलाफ है।

622

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(पैरा 17) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे, विषय दावामे, प्रतिवाद दर्ज करबाक आदेश ओहि दिन देल गेल छल, जखन वादीक विरुद्ध मुकदमा पहिनेसँ खारिज कऽ देल गेल छल आ याचिकाकर्ता, जे प्रतिवादी नं. 1 छथि, के अधिकार पर रोक लगयबाक प्रयास कयल गेल छल। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर जवाबी दावा प्रतिवादी No.1-petitioner के लिए बनाए रखने योग्य नहीं है। वास्तव में, यह गैर-मनोरंजक पाया जाता है, जाहिर है, क्योंकि जवाबी-दावे का मुकदमा चलाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक जवाबी-दावे का सह-प्रतिवादी, जो अपनी माँ द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करता है, विशेष रूप से, जब जवाबी-दावे को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि जवाब दाखिल करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए प्रतिदावे को प्रतिदावे के रूप में चलाने या नए वाद के रूप में माने जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए कोई नहीं। विशाल गर्ग नरवाना और अरिश डीप, एडवोकेट्स, उत्तरदाता संख्या 3 से 5 के लिए।

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, जिससे दिनांकित 08.01.2020 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया गया है, जो अवैध रूप से अधिकार से परे, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना है और आगे एक प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर 11.07.2019 (अनुलग्नक पी-12) दिनांकित आवेदन, जवाबी दावे को खारिज करने के लिए, न्याय के हित में अनुमति दी जाए। (2) ध्यान देने योग्य आवश्यक तथ्य, यहाँ दिए गए क्षेत्र हैंः -कि, प्रारंभ में, प्रत्यर्थी संख्या 1 (विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष वादी) ने प्रतिवादी संख्या 1 (वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता) को अपने आधे हिस्से से अधिक ग्रहणाधिकार, हस्तांतरण या गिरवी रखने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था और आगे अन्य प्रतिवादियों और उनके वकीलों आदि को वाद संपत्ति के किसी भी हिस्से को अलग करने, स्थानांतरित करने या गिरवी रखने से रोकने के लिए, जैसा कि शिकायत के मुख्य नोट में विस्तृत है।

(3) हालाँकि, शिकायत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और क्या हो सकता है

623

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

मुक़दमे के शीर्षक के साथ-साथ संशोधन के आधारों से, आवश्यक वंशावली तालिका को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि यहाँ दिया गया हैः -

केवल कृष्ण शर्मा कमला

कमला देवी (मृत्यु 08.10.2013 पर)

देवी (01.11.1981 पर मृत्यु हो गई)

अशोक के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई

निष्पादन के पक्ष में होगा

कुमार शर्मा 06.01.2006 पर

कमला देवी (उनकी पत्नी) 16.08.1974 पर

राकेश

पूनम

अशोक

सुनीता

नरेश

वीणा

आनंद (आर.

शमा (आर.

सेतुपुत्र

कुमारी

कुमार

कुमार

(आर. नंबर 3)

(पेट।)

सं. 4)

(आर. नंबर 1)

सं. 5)

(आर. नंबर 2)

(5) उक्त संपत्ति अन्य सह-भागीदारों यानी के. के. शर्मा के भाइयों के साथ संयुक्त संपत्ति थी और संपत्ति को पक्षों के बीच विभाजित किया गया था और इस संबंध में उत्परिवर्तन No.1096 के माध्यम से मंजूरी दी गई थी, जो प्रविष्टि जामबंदी में दिखाई दी थी। (6) हालाँकि, पार्टियों की माँ, कमला देवी की मृत्यु 28.10.2013 पर हुई। प्रतिवादी संख्या 1 (याचिकाकर्ता), संबंधित कार्यालय के समक्ष वसीयत पर वादी के अधिकार को विफल करने के लिए, कमला देवी की विरासत के उत्परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए, अपने अनन्य नाम में। वादी को इसके बारे में पता चलने पर संबंधित तहसीलदार के समक्ष आपत्तियां दायर की थीं। इसके अलावा, वाद में यह भी कहा गया था कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1, वसीयत संख्या 1 के अनुसार, समान शेयरों में उक्त संपत्ति के कब्जे में संयुक्त मालिक हैं और वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य प्रतिवादियों से भी अपने दावे को स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इस 624 में स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(8) प्रतिवादी संख्या 3 से 5 (वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 से 5) ने अलग से लिखित बयान दायर किया था, जिससे प्राकृतिक विरासत के आधार पर विचाराधीन संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया गया था। यहां तक कि लिखित बयान का हिस्सा बनाकर प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर किया गया था, जिससे केवल वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों से इनकार किया गया था। उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की थी कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ समान मालिक हैं, जो सभी केवल कृष्ण शर्मा से संबंधित भूमि में अविभाजित हित रखते हैं, जैसा कि प्रति-दावे के पैराग्राफ 15 के खंड (ए) में विस्तृत है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 या वादी को उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से राहत की भी मांग की। (9) इस पृष्ठभूमि में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब मामला 30.11.2018 पर लिया गया था, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः -

“आज वादी के साक्ष्य के लिए और सुबह से बार-बार बुलाए गए मामले की लागत के भुगतान के लिए मामला तय किया गया था, लेकिन वादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

यह अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और

625

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

04.00पीएम। आगे इंतजार करना उचित नहीं है। इसलिए, वादी द्वारा दायर वर्तमान मुकदमे ने यू/ओ9, नियम 8 सी. पी. सी. को खारिज कर दिया। फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी Nos.3 द्वारा 5 पर दायर जवाबी दावा लंबित है। इसलिए, काउंटर दावेदार के साक्ष्य के लिए मामले को 17.12.2018 तक स्थगित कर दिया जाता है। इस न्यायालय के अहलमाद को सी. आई. एस. प्रणाली में जवाबी दावा दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। ”

(13) पीड़ित होते हुए, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है। (14) याचिकाकर्ता ने मूल रूप से प्रति-दावेदारों के साथ सह-प्रतिवादी होने के नाते अपने खिलाफ प्रति-दावा दायर करने को चुनौती दी है।

(15) पक्षों के विद्वान वकील ने सुना।

(16) जवाबी दावा दायर करने से संबंधित प्रावधान सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6ए से 6जी में निहित हैं। तैयार संदर्भ के लिए इसे पुनः प्रस्तुत किया गया है जैसा कि यहाँ दिया गया हैः -

“ प्रतिवादी द्वारा Rule6A.Counter-claim -

1) एक मुकदमे में एक प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, काउंटर 626 के माध्यम से सेटअप कर सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

जहां एक प्रतिवादी एक प्रति-दावा स्थापित करता है और वादी यह तर्क देता है कि वहाँ के दावे को प्रति-दावे के माध्यम से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र मुकदमे में निपटाया जाना चाहिए, वादी, किसी भी समय प्रति-दावे के संबंध में मुद्दों के निपटारे से पहले, एक आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है कि इस तरह के प्रति-दावे को बाहर रखा जा सकता है, और अदालत, ऐसे आवेदन की सुनवाई पर ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे। नियम 6डी। वाद को बंद करने का प्रभाव यदि किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी अतिरिक्त प्रतिवाद करता है, वादी के वाद पर रोक लगा दी जाती है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवाद कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। नियम 6ई। प्रतिदावे का जवाब देने के लिए वादी का चूक।

अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और

627

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

आवेदन करने के लिए लिखित विवरण से संबंधित नियम 6G.Rules प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम जवाबी दावे के जवाब में दायर लिखित बयान पर लागू होंगे। ”

(17) उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वादी के दावे के खिलाफ जवाबी दावा दायर किया जा सकता है और इसे वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में दायर किया जा सकता है। हालांकि, उपरोक्त प्रावधान के आलोक में, मुकदमे में एक प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी, नियम 6ए (3) में निहित प्रावधान के आगे के अवलोकन में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा दायर किया जाता है, तो वादी जवाबी दावे के जवाब में लिखित बयान दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा, नियम 6सी वादी को प्रतिदावे के संबंध में मुद्दे तैयार होने से पहले प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावे पर आपत्ति उठाने का अधिकार देता है और वादी यह दावा कर सकता है कि प्रतिवादी के प्रतिदावे को उसके मुकदमे से बाहर रखा जाए और प्रतिदावे को दायर करने वाला प्रतिवादी, यदि चाहे तो एक अलग मुकदमा दायर कर सकता है। इसी तरह, नियम 6ई में प्रावधान है कि यदि वादी जवाबी दावे का जवाब दाखिल करने में चूक करता है, तो अदालत वादी के खिलाफ, उसके खिलाफ किए गए जवाबी दावे के संबंध में फैसला सुना सकती है। यहां तक कि नियम 6एफ में यह प्रावधान है कि जवाबी दावे में दी जाने वाली राहत वादी के खिलाफ है। (18) यह वादी के खिलाफ दायर किए गए प्रतिदावे के स्पष्ट प्रावधान से संबंधित है। पूरे प्रावधान में, कहीं भी, एक सह-प्रतिवादी पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति को किसी अन्य सह-प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ जवाबी दावा करने की आवश्यकता होती है। संभावित स्थिति में, प्रतिवादी एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा दायर करता है, सह-प्रतिवादी को काउंटर पर लिखित बयान दायर करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है-628

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

आदेश 8 नियम 6ए के तहत दावा, और न ही किसी प्रतिवादी को उसके खिलाफ सह-प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी दावे के बहिष्कार के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, यह सह-प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे के लिए एक लिखित बयान दायर करने के लिए सह-प्रतिवादी के चूक की स्थिति में, एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय की घोषणा के लिए भी प्रदान करता है। इस प्रकार, बिल्कुल, प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (19) इस संबंध में, सोमा देवी बनाम कश्मीरी लाल और अन्य 1 शीर्षक वाले मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का लाभकारी संदर्भ देने के लिए पर्याप्त है, जिसमें उपरोक्त प्रावधानों और सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी दावे के निहितार्थ और सह-प्रतिवादी के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके खिलाफ जवाबी दावा दायर किया गया है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को पैराग्राफ No.15 और 16 में पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त है, जैसा कि यहां दिया गया हैः - “15.इसलिए आदेश VIII नियम 6 ए से 6जी के दावे के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल वादी है; जिसके खिलाफ एक जवाबी दावा अनुमेय है। यह केवल वादी है जिसे जवाबी दावे का जवाब दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। यह केवल वादी है जो इस आधार पर जवाबी दावे की अस्वीकृति के लिए आवेदन कर सकता है कि प्रतिवादी एक अलग मुकदमा दायर कर सकता है और यह केवल वादी है, जिसका लिखित बयान दायर करने में चूक होने पर, न्यायालय वादी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकता है और यह केवल वादी है जिसके खिलाफ कई शेष राशि, जो जवाबी दावे को समायोजित करने के बाद देय पाई जाती है, उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो जवाबी दावा दायर कर रहा है। इसमें अर्थ निहित है, अब यहाँ अभियुक्त-प्रतिवादी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसे किसी अन्य सह-प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ जवाबी दावा करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवादी के मामले में सह-प्रतिवादी को आदेश VIII नियम 6ए के तहत जवाबी दावे के लिए लिखित बयान दायर करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। न ही किसी प्रतिवादी को उसके खिलाफ सह-प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी दावे को हटाने के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार दिया गया है। न ही किसी सह-प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे में लिखित बयान दायर करने में प्रतिवादी की चूक, ऐसे सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय देने के लिए एक आधार के रूप में निर्धारित की गई है। यहां तक कि 1 2017 (4) लॉ हेराल्ड 3362 अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और द्वारा सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे के समायोजन के बाद उसके जीवन का संतुलन भी प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया है।

629

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

सीपीसी। इसलिए, स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 16.यहां तक कि सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावे की अनुमति देने के प्रावधान को भी क़ानून की पुस्तक में इस सरल कारण से नहीं पढ़ा जा सकता है कि इस तरह की निहित धारणा आदेश VIII नियम 6ए से 6जी के अन्य प्रावधानों के पूरी तरह से उल्लंघन में जाएगी। यदि प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी जवाबी दावे पर अदालत द्वारा विचार किया जाता है तो अदालत खुद को एक बेतुकी स्थिति में पाएगी जहां अदालत सह-प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे के खिलाफ लिखित बयान दायर करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं होगी, अदालत सह-प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे को हटाने के लिए एक प्रतिवादी को आवेदन दायर करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं होगी और अदालत सह-प्रतिवादी के खिलाफ राहत देने के लिए अधिकृत नहीं होगी। अदालत के साथ सभी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, फिर से एक निहित अनुमान लगाना होगा कि अदालत के पास ये सभी शक्तियां हैं क्योंकि उसने एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दी है। कानून में अंतर्वेशन और पढ़ने का इतना हिस्सा जो न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है और, बल्कि, व्याख्या के कानून द्वारा निषिद्ध है। कानून बनाने में किसी भी तरह की चूक को विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकरण की ओर से जानबूझकर माना जाना चाहिए। अन्यथा, किसी भी प्रतिवादी को कार्रवाई के किसी भी कारण के लिए सह-प्रतिवादी के खिलाफ एक अलग मुकदमा दायर करने का पूरा अधिकार है। इसलिए, आदेश 8 नियम 6 ए टी ओ 6 जी में शब्दों और वाक्यांशों का ऐसा कोई अंतर्वेशन आवश्यक या अनुमेय नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि एक प्रतिवादी किसी भी परिस्थिति में सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा दायर नहीं कर सकता है। आदेश VIII नियम 6ए से 6जी तक वादी के दावे के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर किए जाने वाले केवल एक जवाबी दावे का प्रावधान और कल्पना करता है। इसलिए वर्तमान मामले में सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा बनाए रखने योग्य नहीं था। ”

(20) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील संख्या 3 से 5 ने भरोसा किया है

झारखंड) और अन्य 2, इस बात पर जोर देने के लिए कि सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रति-दावा बनाए रखने योग्य है। 2 2007 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 674 630

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां राहत पूरी तरह से एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्देशित है, वह पूरी तरह से बनाए रखने योग्य नहीं है। इस संदर्भ में, सोमा देवी के मामले (उपरोक्त) में यह देखा गया कि वादी के खिलाफ दायर जवाबी दावे पर विचार करते समय यह केवल इतना है कि न्यायालय किसी सह-प्रतिवादी के खिलाफ भी कुछ आकस्मिक राहत दे सकता है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी यह निर्धारित नहीं किया था कि सह-प्रतिवादी के पास सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा दायर करने का एक स्वतंत्र उपाय है और उसी के आलोक में, यह देखा गया कि एक प्रतिवादी के पक्ष में एक स्वतंत्र अधिकार बनाना, एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ जवाबी दावा दायर करना, पूरी तरह से अलग मामला है। सह-प्रतिवादी के विरुद्ध आनुषंगिक राहत देने की न्यायालय की शक्ति। हालांकि, राहत अदालत द्वारा दी जा रही मुख्य राहत के लिए विशुद्ध रूप से आकस्मिक होनी चाहिए। (22) दी गई परिस्थितियों में, सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक स्वतंत्र जवाबी दावा, सह-प्रतिवादी की स्वतंत्र क्षमता में बनाए रखने योग्य नहीं है। लेकिन, एक आनुषंगिक राहत के रूप में, मुख्य राहत के लिए, जो शायद वादी के खिलाफ दी गई है, यह अदालत द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, यहां तक कि एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ भी, यदि आवश्यकता हो, तो।

अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा और

631

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(23) सत्येंद्र और अन्य बनाम सरोज और अन्य 3 में, यह था

3 2022 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 89 4 2017 (3) एयर कार आर 209 632

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(28) जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी का मुकदमा आदेश 9 नियम 8 सी. पी. सी. के तहत खारिज कर दिया गया था। केवल इसके बाद, प्रति-दावा दर्ज करने का आदेश दिया गया और प्रति-दावेदारों के साक्ष्य के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया। ऐसी स्थिति होने के कारण, प्रतिस्पर्धा केवल याचिकाकर्ता के अधिकारों पर निर्भर थी, जो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 है और उसे लिखित बयान दायर करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। इन परिस्थितियों में, प्रति-दावा निश्चित रूप से उसके अधिकारों पर एक बादल पैदा करता है, केवल सूट संपत्ति की तुलना में। बहुत ही चतुराई से किए गए कदम के माध्यम से, वादी याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों का विरोध करने के लिए अदालती कार्यवाही से दूर रहा, जिसने, जैसा कि कागजी पुस्तक से स्पष्ट है, विभिन्न न्यायालयों में विरासत के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। (29) जैसा कि अनुलग्नक पी-6 से स्पष्ट है, कुमार शर्मा (जो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष वादी हैं) ने पहले घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिससे उनके सभी भाइयों और बहनों को प्रतिवादी बनाया गया था, जिससे याचिकाकर्ता-प्रतिवादी अशोक कुमार शर्मा बनाम राकेश कुमार शर्मा के साथ खुद को समान हिस्से में मालिक होने का दावा किया गया था।

633

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(30) विषय मुकदमे में, प्रति-दावा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, उस दिन, जब वादी के खिलाफ मुकदमा पहले ही खारिज कर दिया गया था और एक बादल बनाने का प्रयास किया गया था, याचिकाकर्ता के अधिकारों के अनुसार, जो प्रतिवादी संख्या 1 है। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर जवाबी दावा प्रतिवादी No.1-petitioner के लिए बनाए रखने योग्य नहीं है। वास्तव में, यह गैर-मनोरंजक पाया जाता है, जाहिर है, क्योंकि प्रति-दावा सह-प्रतिवादी के रूप में, जो अपने पक्ष में अपनी माँ द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर, पूरी संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करता है, प्रति-दावा करने का कोई सवाल ही नहीं है, विशेष रूप से, जब प्रति-दावा लड़ने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि जवाब दाखिल करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए प्रतिदावे को प्रतिदावे के रूप में चलाने या नए वाद के रूप में माने जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। (31) उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, जवाबी दावे को खारिज करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है।

(32) अतः पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है।

(33) इसके अलावा, किसी भी अन्य मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह देखा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5, जो प्रतिवादी संख्या 3 से 5 हैं, कानूनी उपचार का सहारा लेकर अपनी मां की प्राकृतिक विरासत के आधार पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वादी और प्रतिवादी संख्या 1, (जो भाई हैं) को उपलब्ध आपत्तियों को लड़ने और उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिन्हें संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार, यहां ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। रिपोर्टर-डॉ. सुमती जुंद